



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2019/कार्तिक 7, 1941

No. 340]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2019/KARTIKA 7, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर,

मामला सं. सीबीडी - 07/2019

विषय : कोरिया गणतंत्र से स्टायरिन बुटाडायन रबड़ के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/21/2019-डी जी टी आर.— मैसर्स इण्डियन सेंथेटिक रबड़ प्रा. लिमि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. (इसके बाद याचिकाकर्ता अथवा आवेदक के रूप में भी संदर्भित) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) और समय समय यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन और क्षति का निर्धारण) नियमावली 1995, के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें कोरिया गणतंत्र (इसके पश्चात संबद्ध देश के रूप में संदर्भित) से स्टायरिन बुटाडायन रबड़ (इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) को सब्सिडी दिये जाने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए सब्सिडीरोधी जांच को शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

क. सब्सिडी दिये जाने का आरोप

1. याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को विभिन्न प्रांतों और नगरपालिकाओं जिनमें उत्पादक/ निर्यातक स्थित हैं की सरकार और अन्य 'सार्वजनिक निकायों' सहित संबद्ध देश की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई कार्यवाही योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में यथाउपलब्ध संगत कानूनों, नियमावली और विनियमों तथा संगत सरकारी एजेंसियों और

सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं तथा जांच करने वाले अन्य प्राधिकारियों जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी कार्यक्रमों के होने का निष्कर्ष निकाला है, के निर्धारण में विश्वास किया है।

ख. निष्कर्ष

2. ए एस सी एम के अनुच्छेद 13 के संबंध में, परामर्श के लिए आमंत्रण कोरिया गणतंत्र की सरकार के प्रतिनिधियों को 09.10.2019 और 15.10.2019 को भेजा गया था। हालांकि कोरिया की सरकार ने परामर्श के लिए भेजे गये दो आमंत्रणों के बारे में उत्तर नहीं दिया है।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया प्रथम दृष्टया साक्ष्य यह दर्शाता है कि कोरिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादों और निर्यातकों को कोरिया की सरकार और/ अथवा अन्य सार्वजनिक निकायों जिसकी सूची नीचे दी गई है द्वारा दी गई अनेक सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है।

क. इक्विटी डालने/ निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में पहचान की गई योजना

1. कार्यक्रम सं. 1 : कोरपोरेट पुनर्गठन/ ऋण पुनर्गठन

ख. अप्रत्यक्ष करों के रूप में पहचान की गई योजना

2. कार्यक्रम सं. 2 : गैर भौतिक रूप से शामिल की गई मदों और अत्यधिक हानि दर पर निर्यात/ शुल्क वापसी के लिए कच्चे माल पर शुल्क वापसी – सीमा शुल्क प्रतिदाय

ग. अनुदानों के रूप में पहचान की गई योजनाएं

3. कार्यक्रम सं. 3 : एस बी आर उत्पादकों अथवा निर्माताओं की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सरकारों का अनुदान, तदर्थ सब्सिडी
4. कार्यक्रम सं. 4 : नवीकरणीय उर्जा परियोजना की स्थापना संबंधी नीति
5. कार्यक्रम सं. 5 : विशेष आर एंड डी क्षेत्रों के भीतर अनुसंधान एवं विकास परियोजना समर्थन नीति/ कोरपोरेट कर छूट/ कंपनियों के लिए कटौती

घ. अधिमन्य ऋण के रूप में पहचान की गई योजनाएं

6. कार्यक्रम सं. 6 : कोरिया के औद्योगिक बैंक द्वारा अधिमन्य ऋण
4. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि वे सार्वजनिक निकायों सहित ऐसे संबंधित देश की स्थानीय सरकार अथवा अन्य क्षेत्रीय सरकार अथवा संबंधित संबद्ध देश की सरकार से वित्तीय लाभ को शामिल करती हैं और प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि वे कुछ उपक्रमों अथवा उपक्रम समूहों और/ अथवा उत्पादों और/ अथवा क्षेत्रों तक सीमित है और इसलिए विशिष्ट एवं प्रतिसंतुलनकारणीय है। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में वे आयात की गई वस्तुओं पर घरेलू उपयोग पर निर्भर है और/ अथवा निर्यात कार्यनिष्पादन पर निर्भर है।
5. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसका मौजूद होना पाया जा सकता है और जिसका लाभ जांच के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उठाया जा सकता है।

घ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संबंध

6. याचिकाकर्ताओं ने इस नियमावली के अंतर्गत यथानिर्धारित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मानदंडों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। इन याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से कथित सब्सिडीयुक्त आयातों से हुई है।

ड. जांच की शुरुआत

7. प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकारणीय सब्सिडी के मौजूद रहने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस प्रकार के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमत संबंधी प्रभावों के माध्यम से वास्तविक क्षति हो रही है।
8. उपयुक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 के संबंध में कथित सब्सिडी दिये जाने और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे की जांच शुरू करते हैं जिससे कि कथित सब्सिडी दिये जाने के मौजूद रहने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, जिसे यदि लगाया जाये तो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा कि सिफारिश की जा सके।

च. घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन मैसर्स इण्डियन सिंथेटिक रबड़ प्रा. लिमि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. जो संबद्ध वस्तुओं का मात्र उत्पादक हैं और इस कारण से कुल भारतीय उत्पादन की स्थिति को बताता है, द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता स्थिति को पूरा करते हैं और इस नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं।

छ. विचाराधीन उत्पाद

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एस बी आर 1500 और एस बी आर 1700 सीरीज का एमल्शन स्टायरिन बुटाडायन रबड़ इसके पश्चात “इ-एसबीआर” के रूप में संदर्भित है।
11. इसे दो मोनोमर्स अर्थात् स्टारिन बुटाडायन से प्राप्त किया जाता है। दो मोनोमर्स से पोलिमर बनाने का कार्य दो प्रक्रियाओं अर्थात् घोल (एस-एसबीआर) और एमल्शन (ई-एसबीआर) के द्वारा किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एस बी आर तक सीमित है जो एमल्शन प्रक्रिया अर्थात् ई - एस बी आर से निकलता है।
12. इस उत्पाद का प्राथमिक उपयोग टायरों और टायर रिट्रिड कम्पाउंड्स में किया जाता है। ई - एस बी आर के उपयोग के अन्य क्षेत्र हाउसवेयर वेयर मेट्स, ड्रेन बोर्ड ट्रे, शू शोल और हील्स, चिविंगम, फूड कोटेनर सिलेंट्स, ट्रे, कन्वेयर बेल्ट, स्पोंज आर्टिकल, अधेसिव्स और काल्कस, ऑटोमोबाइल्स मेट्स, ब्रेक एंड क्लच पेड्स, होज, वी-वेल्ट्स, फ्लोरिंग, मिट्टरी टैंक पेड्स, हार्ड रबड़ बैट्री बॉक्स केस, एकटूडेड गैसकिट, रबड़ टॉय, मोल्डेड रबड़ गूड्स, शू शोलिंग, केबल इंसुलेशन और जेकेटिंग, फार्मासिटिकल, सर्जिकल और सेनेटरी प्रॉडक्ट, फूड पैकेजिंग आदि शामिल हैं।
13. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण उक्त शीर्ष 400219 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ज. समान वस्तु

14. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई वस्तु संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं। यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित की गई तथा संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु में बहुत अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबंध वस्तु को संबद्ध देश आयात की गई संबद्ध वस्तु के ‘समान वस्तु’ के रूप में माना जा रहा है।

झ. शामिल किया गया देश

15. वर्तमान जांच के उद्देश्य से शामिल किया गया देश कोरिया गणतंत्र है।

ञ. जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 महीने) है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और जांच की अवधि शामिल रहेगी।

ट. प्रक्रिया और सूचना का प्रस्तुतिकरण

17. उत्पादन और घरेलू उद्योग से संबंधित संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचना दी जा रही है ताकि वे निर्धारित रूप में और तरीके से सभी संगत सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें। वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति भी निम्नलिखित को लिख सकते हैं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य विभाग****वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय****चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग,****5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001**

18. उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और ताकि वे उपभोक्ता संगठनों जो सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, जो सन्निही, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत हो, का प्रतिनिधित्व कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमाओं के भीतर जांच से संगत अपना अनुरोध कर सकता है।

ठ. समय सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि वह प्राधिकारी को ऊपर में उल्लिखित पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 40 (चालीस) दिनों के भीतर पहुंच सके। हालांकि, संबद्ध देश की सरकार, ज्ञात निर्यातक और आयातक जिनका पृथक रूप से पता दिया जा रहा है, से यह अपेक्षित है कि वे पृथक रूप से उन्हें भेजे गये पत्र की तिथि से 40 (चालीस) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्रस्तुत की गई सूचना अपूर्ण होती है तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकार्ड कर सकते हैं।

ड. अगोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतिकरण

20. इस नियमावली के नियम 8 के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना के अगोपनीय पाठ को प्रस्तुत करें। यदि गोपनीयता का दावा प्रश्नावली के उत्तर/ अनुरोधों के किसी हिस्से के संबंध में किया जाता है तब उसे दो अलग अलग सेट (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक/ विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय के रूप में चिह्नित दूसरा सेट (शीर्षक/ विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दी गई सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ शीर्ष पर या तो 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' के रूप में चिह्नित होना चाहिए।
21. 'गोपनीय' के रूप में किसी चिह्न के बिना दी गई सूचना को 'अगोपनीय' के रूप में माना जाना चाहिए और प्राधिकारी के पास यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार की किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति दें। गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
22. गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना के लिए, सूचना के आपूर्तिकारों से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है और/ अथवा क्यों इस प्रकार की सूचना का संक्षेपण संभव नहीं है।
23. अगोपनीय पाठ उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर करते हुए अधिमान्य रूप से सूचीबद्ध अथवा खाली/ संक्षिप्त रूप से गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिलिपि होनी अपेक्षित है।

अगोपनीय संक्षेपण पर्याप्त विवरण के साथ होना चाहिए जिससे कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के तथ्य को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि इस प्रकार की सूचना का संक्षेपण नहीं किया जा सकता है; कारणों का विवरण कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

24. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसको प्रकट करने का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है तब वे इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
25. कोई अनुरोध जिसे उसके सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिये बिना किया गया हो, तब उसे प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता के लिए आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इसे इस प्रकार की गोपनीय सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

ढ. असहयोग

26. नियम 7(8) के संबंध में, उस स्थिति में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना के संबंध जानकारी दिये जाने से इनकार करता है अथवा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने इसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को इस सरकार की सिफारिशें कर सकते हैं जिसे उसके द्वारा उपयुक्त माना गया हो।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 7(7) के संबंध में, कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अगोपनीय पाठ हों, का निरीक्षण कर सकता है।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2019

Case No. CVD-07/2019

Subject: Initiation of Anti-Subsidy Investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber from Korea RP.

F. No. 6/21/2019-DGTR.—M/s Indian Synthetic Rubber Pvt Ltd and M/s Reliance Industries Ltd (hereinafter also referred to as the Petitioners or Applicants) have filed an application before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules), alleging subsidization of Styrene Butadiene Rubber (hereinafter also referred to as the subject goods), from Korea RP (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Allegation of Subsidization

1. The petitioners have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Governments of the subject country, including the

government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public bodies'. The petitioners have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who had conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

B. Consultation

2. In terms of Article 13 of ASCM, invitation for consultations was sent to the representatives of the Government of Korea RP on 09.10.2019 and 15.10.2019. However, the Government of Korea has not responded on the two invitations sent for consultation.

C. Subsidy Programs

3. The prima facie evidence provided by the petitioners shows that the producers and exporters of the subject goods in Korea have benefitted from a number of subsidies granted by the Government of Korea and/or other public bodies as listed below:

A. Scheme identified in form of Equity infusion/direct transfer of funds

1. Program No 1: Corporate restructuring /Debt restructuring

B. Scheme identified in form of indirect taxes

2. Program No 2: Duty draw back –Refund of customs duties on raw materials for exports / Duty Drawback on Non-Physically Incorporated Items and Excess Loss Rate

C. Schemes identified in form of Grants

3. Program No 3: Various government grants as per the Annual report of SBR producers or manufactures Ad-hoc Subsidies
4. Program No 4: Renewable Energy Projects Set-up Policy
5. Program No 5: Research & Development Projects Support Policy/ Corporate Tax Exemption/Reduction for Companies within Special R&D Zones

D. Schemes identified in form of Preferential lending

6. Program No 6: Preferential lending by Industrial Bank of Korea

4. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of the respective subject country or other regional or local government of such respective country, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.
5. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during investigation.

D. Allegation of Injury and Casual Link

6. The petitioners have furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the petitioners' prima facie shows material injury to the domestic industry has been caused by the alleged subsidized imports from the subject country.

E. Initiation of the Investigation

7. The Authority finds that there is prima facie evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject country and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their price effects
8. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury and threat of injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic Industry

9. The application has been filed by M/s Indian Synthetic Rubber Pvt Ltd and M/s Reliance Industries Limited, which are the only producers of subject goods and therefore, accounts for total Indian production. The petitioners satisfy the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

G. Product under consideration

10. Product under consideration in the present investigation is Emulsion Styrene Butadiene Rubber (hereafter referred to as "E-SBR") limited to SBR 1500 and SBR 1700 series.

11. It is derived from two monomers namely styrene and butadiene. The polymerization of the two monomers is done through two processes namely, solution (S-SBR) and emulsion (E-SBR). The product under consideration in the present investigation is limited to the SBR that comes out from emulsion process i.e. E-SBR.
12. The product finds its primary usage in the production of tires and tire retread compounds. The other areas of usage of E-SBR include house ware mats, drain board trays, shoe sole and heels, chewing gum, food container sealants, tires, conveyor belts, sponge articles, adhesives and caulks, automobiles mats, brake and clutch pads, hose, V-belts, flooring, military tank pads, hard rubber battery box cases, extruded gaskets, rubber toys, molded rubber goods, shoe soling, cable insulation and jacketing, pharmaceutical, surgical, and sanitary products, food packaging, etc.
13. The product under consideration is classified under Chapter 40 of Customs Tariff Act, 1975 under subheading 400219. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the investigation.

H. Like Article

14. The petitioners have claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from the subject country. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from subject country. The petitioners claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like articles' of the subject goods imported from the subject country.

I. Country Involved

15. The country involved for the purpose of current investigation is Korea RP.

J. Period of Investigation

16. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2018 to March 2019 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the POI.

K. Procedure & Submission of information

17. The exporters in the subject country, importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being informed separately to enable them to provide all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may also write to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

18. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and casual link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limits set out below.

L. Time limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of subject country, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

M. Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any mark as “Confidential” shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible
23. The non- confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information

N. Non cooperation

26. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

O. Inspection of Public File

27. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Designated Authority